

अंतरराष्ट्रीय कानून का भ्रमः शक्ति, दण्डमुक्ति और जंगल

आधुनिक विश्व की दुखद वास्तविकता यह है कि नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था एक खोखला दिखावा है, जो कच्ची शक्ति के तले ढह रहा है। यह कहीं और से अधिक स्पष्ट इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के फिलिस्तीनियों के खिलाफ अभियान के मामले में है, जिसे सामूहिक हत्या और आतंकवाद के रूप में वर्णित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय कानूनी संस्थाओं जैसे ICC, ICJ और UNGA के बावजूद, ये संस्थाएं शक्तिशाली राज्यों और उनके सहयोगियों के खिलाफ शक्तिहीन हैं। गिरफ्तारी वारंट, फैसले और प्रस्ताव प्रतीकात्मक इशारे हैं, जो कोई परिणाम नहीं लाते। नेतन्याहू जैसे व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून शून्य है, और वैश्विक व्यवस्था जंगल के कानून द्वारा शासित है, जहां शक्ति ही सही है और मानव सभ्यता बर्बरता पर एक पतली परत है।

ICC, जो युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के अभियोजन के लिए स्थापित किया गया था, शक्तिशाली व्यक्तियों का सामना करने में निष्प्रभावी है। यह नेतन्याहू या उनकी सरकार के लिए वारंट जारी कर सकता है, लेकिन इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। पश्चिमी नेता, जो अपनी बयानबाजी में ICC के मिशन का समर्थन करते हैं, कार्रवाई करने की इच्छा की कमी रखते हैं। अमेरिका, इजरायल का सहयोगी, संयुक्त राष्ट्र में वीटो या दबाव के जरिए उसकी रक्षा करता है। अन्य पश्चिमी राष्ट्र, तनावों से सतर्क, इसका अनुसरण करते हैं, जिससे ICC के प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। न्याय चयनात्मक है, जो उन लोगों पर लागू होता है जिनके पास शक्ति नहीं है। फिलिस्तीनियों के लिए, जो दशकों से हिंसा और उत्पीड़न सह रहे हैं, ICC की विफलता यह याद दिलाती है कि कानून शक्तिशाली के सामने झुकता है।

ICJ, जिसे राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने और राय देने का कार्य सौंपा गया है, उतना ही शक्तिहीन है। यह इजरायल के कार्यों—बस्तियों, कब्जे, या गाजा में बल प्रयोग—की निंदा कर सकता है, लेकिन इसके फैसले बिना वजन के हैं। अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों द्वारा समर्थित इजरायल, बिना डर के ICJ को नजरअंदाज करता है। अदालत की बाध्य करने में असमर्थता सैन्य और कूटनीतिक प्रभाव के सामने अंतरराष्ट्रीय कानून की नाजुकता को उजागर करती है। फिलिस्तीनियों के लिए, ICJ के फैसले नैतिक जीत हैं, जो उस दुनिया में क्षणिक हैं जो उत्पीड़कों को जवाबदेह ठहराने से इनकार करती है। हिंसा जारी रहती है, क्योंकि कानून एक खाली वादा साबित होता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा, अपने लोकतांत्रिक स्वरूप के बावजूद, कानून की नपुंसकता को दर्शाती है। इसने इजरायल के कार्यों—कब्जे, गाजा की नाकेबंदी, नागरिकों की हत्या—की निंदा करते हुए अनगिनत प्रस्ताव पारित किए हैं। ये प्रस्ताव, जो बहुमत द्वारा समर्थित हैं, इजरायल के उल्लंघनों पर वैश्विक सहमति को दर्शाते हैं। फिर भी, ये गैर-बाध्यकारी हैं और प्रवर्तन की कमी रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जहां वास्तविक शक्ति निहित है, अमेरिका के वीटो द्वारा पंगु है, जो इजरायल की रक्षा करता है। महासभा के प्रस्ताव इशारे हैं, जो बिना पढ़े ढेर हो जाते हैं। फिलिस्तीनियों के लिए, ये कोई राहत नहीं देते, न ही दण्डमुक्ति वाले राज्य द्वारा किए गए दुखों का अंत करते हैं।

निहितार्थ भयावह हैं: नियम-आधारित व्यवस्था मृत है। न्याय, समानता और जवाबदेही शक्तिशाली के लिए काल्पनिक हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी, जो स्वयं को नैतिक संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कानून के चयनात्मक अनुप्रयोग में पाखंड को उजागर करते हैं। वे तब संस्थाओं का समर्थन करते हैं जब यह उनके अनुकूल होता है, और उन्हें नजरअंदाज करते हैं जब यह नहीं होता। यह दोहरा मापदंड वैश्विक दक्षिण के लिए स्पष्ट है, जो व्यवस्था को वर्चस्व के एक उपकरण के रूप में देखता है। फिलिस्तीनी संघर्ष एक सूक्ष्म विश्व है: दुनिया शक्ति द्वारा शासित है। नेतन्याहू को जवाबदेह ठहराने में विफलता एक लक्षण है—एक ऐसी दुनिया का, जहां कानून शक्तिशाली का हथियार है, न कि कमजोरों के लिए ढाल।

मानव सभ्यता, प्रगति और अधिकारों के आदर्शों के साथ, नाजुक है। फिलिस्तीनियों का दुख, जो उदासीनता के साथ मिलता है, एक सभ्य व्यवस्था की अनुपस्थिति को रेखांकित करता है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां शक्ति सत्य को निर्धारित करती है, मजबूत अत्याचार करते हैं, और कमजोर न्याय के लिए भीख मांगते हैं। नेतन्याहू की सरकार को जवाबदेह ठहराने में

विफलता एक गहरी बीमारी को उजागर करती है—एक ऐसी दुनिया जहां जंगल का कानून राज करता है और सभ्यता एक मिथक है।

निष्कर्ष में, नेतन्याहू के तहत फिलिस्तीनियों की दुर्दशा अंतरराष्ट्रीय कानून की खोखलापन और नियम-आधारित व्यवस्था के मिथक को उजागर करती है। ICC के वारंट, ICJ के फैसले और UNGA के प्रस्ताव पश्चिमी कार्रवाई के बिना और अमेरिका के इजरायल समर्थन के साथ अर्थहीन हैं। वैश्विक व्यवस्था, जो सभ्य होने से कोसों दूर है, शक्ति के आधार पर संचालित होती है। फिलिस्तीनियों के लिए, यह हिंसा और निराशा की जीवंत वास्तविकता है। जंगल का कानून राज करता है, और जब तक दुनिया इस वास्तविकता का सामना नहीं करती, तब तक न्याय एक सपना बना रहेगा, जो उन लोगों की पहुंच से बाहर है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।